

एक विशेष घटना की ओर दिलाना चाहता हूँ। ठाणे जिले के शहापुर तहसील में आटगांव नाम का एक गांव है। पिछले हफ्ते में वहाँ जो विशेष घटना हुई उसका मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। ठाणे जिले में आटगांव के रैज्वै स्टेशन से डेढ़ से दो कि०मी० के फासले पर दो पहाड़ों के बीच में करीब करीब एक हजार साल पुराने दो शिव मंदिर थे। उसमें से एक मंदिर चोरी हो गया है। इस मंदिर को उसके नीचे के साथ चोरी किया गया है। यह एक अचरजवाली बात है। इस घटना से वास्तुकला विशेषज्ञ अचरज में पड़ गये हैं। साथ-साथ इस क्षेत्र की जनता को एक आघात पहुंचा है।

इस मंदिर की चोरी के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है। वह रहस्य यह है कि इस मंदिर के पत्थरों पर उच्च कोटि की नक्काशी की गयी थी। इस नक्काशी को देखकर वास्तुकला विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया था कि यह मंदिर 1000 साल पुराना है। शिलाहार राजाओं के समय में इस मंदिर को बनाया होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक बाम्बे गल्टियर में भी इसका उल्लेख है। कब यह मंदिर भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के अधीन था।

इस मंदिर के चोरी के पीछे कोई पड्यंत्र भी हो सकता है। इसलिये सरकार को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिये और इस घटना की पूरी जांच की जानी चाहिये। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं इसके लिये इस घटना की पूरी जांच होनी चाहिये। चोरी किये गये मंदिर के पत्थरों को हस्तगत करके पुरातत्व विभाग ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करना चाहिये।

Inauguration of Metro Channel  
in Ahmedabad

श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल  
(गुजरात) : महोदया, एक मई के दिन केन्द्र सरकार के ब्रॉड कास्टिंग मिनिस्टर

\*मूल मराठी भाषा का हिन्दी अनुवाद :

श्री के. पी. सिंह देव अहमदाबाद आए थे। लाखों रुपये खर्च करके मेट्रो चैनल का उद्घाटन का बड़ा समारोह किया था। लाखों रुपये खर्च करके लाइव टेलीकास्ट किया गया था। लेकिन अहमदाबाद नगर की जनता पिछले तीन दिन से टी.वी. पर मेट्रो चैनल बूंद रही है। अब तक किसी को मेट्रो चैनल हाथ नहीं लभ रही है। लोग आम तौर पर बोल रहे हैं कि अहमदाबाद में मेट्रो चैनल का बोफोर्स हो गया है। आज अहमदाबाद दूरदर्शन की ओर से लोगों को सूचना दी गई है कि मेट्रो चैनल देखना चाहते हैं तो 50 फुट से भी ऊंचा बड़ा एन्टीना लगाना पड़ेगा। अगर यही हालत है तो मध्यम वर्ग के व्यक्ति को तीन चार हजार रुपये का एन्टीना खरीदने के लिए मजबूर करने की ये साजिश क्यों की गई? क्या उत्पादन करने वाले लोगों के साथ सरकार में बैठे हुए लोगों का कोई गठबन्धन है? मेट्रो चैनल चलाना ही था तो फिर तो पावर ट्रांसमिशन मशीन क्यों उपयोग में लाया गया? तीस लाख की जनता को भी जो चैनल दिखाई न दे और जोर शोर से चैनल शुरू करने का उद्घाटन समारोह किया जाए ऐसा जनता को गुमराह करने का कितना शोभास्पदा है। क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जिन योजनाओं को शुरू करे उनका लाभ जनता की ही मिले, सिर्फ उद्घाटन करने वालों को नहीं?

मेरी मांग है कि तत्काल शुरू की गई मेट्रो चैनल सामान्य आदमी देख सके इस प्रकार की टैक्नीकल व्यवस्था बनाई जाए। धन्यवाद।

I. S. I. Activities in Delhi and Uttar  
Pradesh

डा० मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश) : उपसमाध्यक्ष महोदया, मैं इस विशेष उल्लेख के द्वारा एक बड़े गंभीर प्रश्न की ओर सदन का और शासन का ध्यान आकषित करना चाहता हूँ। पिछले दिनों आदर्श नगर दिल्ली में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 खतरनाक सदस्य मुश्ताक अहमद, अब्दुल रहीद और मोहम्मद सुमान चंया गिरफ्तार हुए।

उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जो पूछताछ की उससे बड़े चौकाने वाले तथ्य सामने आए। राजधानी और उसकी सीमा के पास अब आई.एस.आई. के एजेंट सक्रिय हैं। यह एक खतरनाक बात है और केन्द्र सरकार को तथा गृह मंत्रालय को इस बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए। यह भी रिपोर्ट बराबर अखबारों में आई है कि गृह मंत्रालय के पास इस बात के पूरे प्रमाण हैं कि आई.एस.आई. के द्वारा भेजे गए आतंकवादी अब अलीगढ़, मुरादाबाद, कानपुर, गाजियाबाद जैसे शहरों में अड़े बनाए हुए हैं। दिल्ली महानगर में भी आई.एस.आई. की गतिविधियों में वृद्धि के समाचार मिले हैं। गृह मंत्रालय ने मुलायम सिंह सरकार को इस बारे में सूचित किया था। मैं जानना चाहूंगा कि गृह मंत्रालय ने क्या सूचना उन्हें दी थी, क्या निर्देश दिए थे कि वह इस बारे में अपने प्रशासन को चुस्त रखें? लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रशासन द्वारा मुलायम सिंह की सरकार के द्वारा इस मामले में कोई कदम अभी तक उठाया गया और नौएडा, पिलखुआ, मेरठ, रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, कानपुर, इलाहाबाद अभी तक बहुत सेंसेटिव, अति संवेदनशील बने हुए हैं। आई.एस.आई. के एजेंट हथियारों की तस्करी में भी लगे हुए हैं। भारत-नेपाल सीमा पर ऐसी कई मामले पकड़े गए हैं। गुजरात के कच्छ के इलाके में भारी मात्रा में आई.एस.आई. के एजेंट मादक पदार्थ, हथियार और विस्फोटक पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अपहरण की घटनाओं में वृद्धि है उसके बारे में भी यह संदेह किया जाता है कि अपहरणकर्ताओं के संपर्क आई.एस.आई. के साथ लगातार रहे हैं। हजारों मामले ऐसे भी हैं कि जिनमें पाकिस्तान से वैध रूप में आए लोग अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी वापस नहीं गए और इनकी बड़ी संख्या मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मेरठ और गाजियाबाद के क्षत्रों में है। यह केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की भी सूचना है। इन क्षेत्रों में ये हथियारों और विस्फोटक पदार्थों का संग्रह आई.एस.आई.

के एजेंटों ने किया है, यह समाचार-पत्रों में छपा है। रिपोर्ट यह भी है कि इंडेली-जंस ब्यूरो ने गृह मंत्रालय को सूचित किया है कि जो सहयोग इस ब्यूरो को उत्तर प्रदेश सरकार से मिलना चाहिए वह नहीं मिला है और वहां का स्थानीय प्रशासन इन तस्करों से निवटने में डिलाई बरत रहा है। इसी तरह के समाचार उत्तर पूर्वोत्तर के बारे में भी मिले हैं। आई.एस.आई. का संपर्क बंगलादेश की खुफिया एजेंसी से भी होने की रिपोर्टें हैं।

इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि गृह मंत्रालय की इस समस्या से निवटने के लिए कोई नीति, कोई कार्यक्रम देश भर को सामने रखते हुए बनाया है या नहीं बनाया है?

महोदया, मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण दस्तावेज की तरफ भी दिलाना चाहता हूँ।—जो टॉस्क फोर्स ऑन टेरेरिज्म गूड अन-कन्वेंशनल वार फेयर पर पर-पब्लिकन रिसर्च कमेटी, यू.ए. हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने फरवरी, 1 1993 की पेश की थी उस रिपोर्ट के 40वें पृष्ठ पर यह लिखा हुआ है कि:

"Among the most crucial activities of the ISI were the following:—

'Religious fundamentalism was propagated in small lethal doses to promote separatism and communal outlook.'

SHRI JAYANTHI NATARAJAN  
(Tamil Nadu); Madam, it cannot be read out.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI:  
These are not the proceedings of the House.

**उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खासंडे) :**  
जोशी जी, स्पेशल मेंशन के लिए हमने 3 से 4 मिनट रखे हैं अगर आप पूरा डाक्यूमेंट पढ़ने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगी

**डा० मुरली मनोहर जोशी :** मैडम, मैंने जितना पढ़ना था, उतना पढ़ दिया

'Training and indoctrination of selected leaders from the Kashmir Valley was arranged to create militant cadres.

'A large number of youth from the Kashmir Valley and Poonch Sector were given extensive training in the use of automatic weapons, sabotage and attacks on security forces. Automatic weapons and explosives were now issued to these people.'

'Special teams were trained to organise agitations and hartals, and to engineer incidents to damage the democratic and secular image of India'.

महोदया, मेरा अनुरोध होगा और सरकार से मांग होगी कि इन प्रमाणों और इन तमाम घटनाओं को देखते हुए इस देश में आई.एस.आई. के ड्रैगनेट को तोड़ने के लिए और इन पंचमासी तत्वों से देश को बचाने के लिए गृह मंत्रालय को तुरन्त कठोर कदम उठाने चाहिए और यदि उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह सरकार इस विषय में कड़ी कार्यवाही नहीं कर रही है, तो उत्तर प्रदेश को जलने से बचाने के लिए केन्द्रीय सरकार को आगे आना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोजबाई) :  
धन्यवाद। श्री गोविन्द राव आदिक।

#### Increase in Consumer Price Index and Rate of Inflation

SHRI GOVINDRAO ADIK (Maharashtra):  
Madam, I would like to draw the attention of the Union Government to a very important issue regarding increase in the Consumer Price Index and the rate of inflation.

There has been a constant rise in the Consumer Price Index and inflationary trend in the economy of the country since the reforms process commenced in July 1991. The Consumer Price Index depends on the Wholesale Price Index. The official 'all commodities' WPI, base year 1981-82 is equal to 100, rose to about 258 in April, 1994, Inflation has crossed

the double-digit figure and it may further rise to 12 per cent, the level at which the reforms process had commenced. This trend poses a dangerous signal to the country's economy in more than one way and it may have serious repercussions, it may lead to a further increase in the fiscal deficit, decline in savings, decrease in demand, lowering of industrial production, less job opportunities and sufferings to the common man.

In case the monsoon fails, the inflation might have a paralysing effect on the economy giving rise to many socioeconomic problems. It may upset the reforms process.

Yet another result of the inflationary situation will be further reduction in per capita expenditure on social services — education, health, housing and social security — by the Central Government and the State Governments.

Actually, the inflationary pressure since August 1993 has been attributed to several factors such as the raising of the procurement prices, absence of check on the Government expenditure, pre-budget hikes in the prices of essential commodities in January, 1994, rise in Railway fares and freight and effective increase in the Excise Duty in the main budget. Also, fiscal deficit of over Rs. 58,000 due to decline in Customs and Excise collections and failure to disinvest PSU equity and pile-up of forex reserves of the order of 15 million dollars necessitating the Reserve Bank of India's intervention in the market to keep the rupee from appreciating, have contributed to excess liquidity in the system. All these factors have been responsible for five rise in inflation.

Then the Government's concern at the inflationary situation is natural. It has allowed free import of sugar, edible oil and cotton under OGL. The Government has also contracted forth import of sugar and edible oil. However, this will have only a little impact on the domestic prices in view of the prevailing international prices. But the better strategy would have